THUNGON): (a) and (b) Talks were hrld in March 1993 on shareing the rvier waters between India and Bangladesh during the meeting of Indo-Bangladesh Joint Committee of Experts. The two sides held in-depth discussions to work for an equitable, long term and comprehensive arrengement for sharing the flows of Ganga, Tista and other major rivers.

Conservation of flood value in the coastal areas of T. N.

2255. SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal from the Tamil Nadu Government for conservation of flood waters in the coastal areas;

(b) whether the Ministry has taken into consideration of joining the flood rivers to be collected and stored up to meet the need of water during drought conditions; and

(c) if not, the reasons thrrefor?..

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No such proposal has been received.

(b) and (c) A National Perspective for Water Rrsources Development prepared by Government envisages inter-linkages between various Peninsular rivers and Himalayan rivers separfatel for transfer of water from water rich basms to water short basins for optimum utilisation of water resources. Government has established National Water Development Agency (NWDA) in 1982 for firming up these proposals. A total of 36 water transfer links 17 under peninsular component and 19 under Himalaya component have been identified by National Water Development Agency.

Construction of Dehang and Subansiri reservoir Projects

2256. SHRI DAVID LEDGER: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the recommendations of the Brahmaputra Board for construction of the Dehang and Subansiri Reservoir projects have been accepted by the Central Government;

(b) if so, when thr projects are likely to be launched; and

(c) if the answer to part (a) above in the negative the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) Detailed reports for Dihang and Subannsiri projects could not be finalised as surveys and invrstigations could not be fully carried out for want of permission from the Government of Arunachal Pradesh.

Setting up of National Ground water Institute

2257. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the side Selection Committee for setting up of "National Ground Water Institute has submited its report; and

(b) if so, what are the recommendations of the Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes Sir.

(b) Main recommendations of the Site Selection Committee constitut-

ed by the Government to select the most appropriate site for the National Training Institute for Ground Water spell out the hsuitability of each site offered by the various State Goverhments/Union Territory of Chandigarh keeping in view the criteria like cost of land, infrastructural facilities available, scope of assistance and administrative support to be made available by te concerned State Government etc.

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्य

2258. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के जनजातीय क्षेत्रों के सिंचाई-कार्य संबंधी कार्यक्रम का सरकार द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार जनजातीय क्षेत्रों में किए गए इन कार्यों की समीक्षा किस प्रकार करने का विचार रखती है जिससे यह पता लगाया जा सके कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास-कार्य प्रगति पर है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई विकास सामान्यतया लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से होता है। तथापि, कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में भी सिंचाई प्रदान करने के लिए वृहद माध्यम परियोजनायें शुरू की हैं । चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है, अतः इन परियोजनाओं/योजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । ऐसे कार्यक्रमों के पुनरीक्षणमूल्यांकन हेतु उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल है :

(i) आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत वृहद एव मध्यम सिंचाई कार्यों का प्रबोधन ।

(ii) कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक साथ मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार के अधिकरियों द्वारा मौके पर जांच ।

(iii) गैर-सरकारी तथा अनुसधान सगठनों द्वारा अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रभावित सिंचाई परियोजनायें

2259. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रभावित हुई है ;

(ख) कौन-कौन सी परियोजनायें अधूरी रह गई हैं, वर्ष 1980 के पूर्व इनका कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी ;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) गुजरात की सिंचाई परियोजनायें जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण पूरी नहीं की जा सकी, का ब्यौरा निम्नवत है :